

कक्षा 8 राजनीति विज्ञान अध्याय 7 जनसुविधाएं Notes

- समृद्ध क्षेत्रों - बंगलों में और आसपास छिड़कने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी - यदि कमी है - तत्काल पानी के टंकी उपलब्ध कराए जाते हैं।
- अन्य क्षेत्रों - बोरेवेल पानी (खारा पानी - पीने योग्य नहीं) - जल शुद्धिकरण पद्धति
- अन्य क्षेत्रों - लोगों को बोतलबंद पानी मिलता है - पानी 4 दिनों में एक बार मिलता है।
- झोपड़ियां - आम नल में (20 मिनट के लिए पानी उपलब्ध - दिन में दो बार - प्रति परिवार अधिकतम सीमा 3 बाल्टी है) और आम शौचालय - पानी के लिए लंबे समय तक

आधारभूत अधिकार के रूप में पानी

- जीवन के लिए आवश्यक है।
- सुरक्षित पीने का पानी - पानी से संबंधित बीमारियों को रोकना।
- पानी से संबंधित बीमारियों के कारण 5 साल से कम उम्र के 1600 बच्चे रोज मर जाते हैं।
- भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा होने के नाते पानी के अधिकार को मान्यता देता है।
- 2007: आंध्र प्रदेश महान्यायालय - महाबूबनगर जिले के एक ग्रामीण द्वारा लिखे गए एक पत्र के आधार पर एक मामला सुनकर एक कपड़े की मिल द्वारा पीने के पानी के प्रदूषण पर जो कि अपने गांव के पास एक धारा में जहरीले रसायनों को निर्वहन कर रहा था (जिलाधीश ने 25 लीटर की आपूर्ति करने का आदेश दिया प्रत्येक व्यक्ति को पानी प्राप्त होगा)

सार्वजनिक सुविधाएं

Public Facilities

- स्वास्थ्य देखभाल
- स्वच्छता - 68% घरों में भारत में पीने के पानी की पहुंच है और 36% की स्वच्छता तक पहुंच है।
- विद्युत
- सार्वजनिक परिवहन - महानगरों के लिए बसें (दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपये), मुंबई उपनगर - 65 लाख यात्रियों दैनिक यात्रा करते हैं।
- पाठशालाएं और महाविद्यालय
- कई लोगो द्वारा लाभ को बांटा जा सकता है।

सरकार का योगदान

- किसी को इसे लोगों को प्रदान करने की जिम्मेदारी लेना - सरकार
- निजी कंपनियां लाभ के लिए काम करती हैं - कक्षा 7 में अध्याय "शर्ट की कहानी"

- निजी कंपनियों द्वारा पानी की टंकी- निजी कंपनियां सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं लेकिन कीमत पर लेने की वजह से केवल कुछ लोग ही खर्च कर सकते हैं।
- जो लोग भुगतान नहीं कर सकते वे इससे वंचित रह जायेंगे- सरकार इसका ख्याल रखती है।
- केंद्र सरकार ब्याज, सुरक्षा, सहायिकी, आर्थिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, अनुदान, पुलिस इत्यादि पर खर्च करती है।
- बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है- सरकार का खर्च और कितना खर्च करने की योजना इसमें होती है।
- राज्य की आय के स्रोत - महसूल से, पानी पर किये जानेवाले खर्च से आते हैं।

पानी पहुंचाने की व्यवस्था

- निकट क्षेत्र - ज्यादा पानी
- दूर इलाके में - कम पानी
- नगर आपूर्ति में केवल आवश्यकता का आधा पानी मिल पाता है।
- कमी का बोझ - गरीबों पर पड़ता है।
- मध्यम वर्ग - बोरेवेल की खुदाई, बोटलबंद पानी खरीदना, टैंकर खरीदना
- 'पर्याप्त और सुरक्षित' पानी तक सार्वभौमिक पहुंच
- नजदीक के स्थानों से शहरी इलाकों में आने वाला पानी - आस-पास के स्थानों में भूजल के स्तर गिर गए हैं।

पानी के विकल्प

- निजी संगठनों के विस्तार से पानी तेजी से भरा जा रहा है जो लाभ के लिए पानी बेच रहे हैं ...
- पानी के उपयोग में बड़ी असमानताएं
- शहरी क्षेत्र में पानी / व्यक्ति की आपूर्ति - भारत में शहरी जल आयोग के रूप में 135 L/ दिन (लगभग सात बाल्टी) - झोपड़ियों के लिए यह 20 L / दिन (एक बाल्टी) से कम है और महंगी होटल के लिए यह 1,600 L / दिन है (80 बाल्टी) ।
- नगर निगम के पानी की कमी - सरकार का संकेत असफलता मिली।
- दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वजनिक जल आपूर्ति ने सार्वभौमिक पहुंच हासिल की है - पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील - कम शिशु मृत्यु - औसत मूल्य कम है और गरीबों का आधा दर पर शुल्क लिया जाता है - विभाग का कार्य पारदर्शी होता है और वे प्राथमिकताओं पर मत देते हैं।
- निजी कंपनियों को दिए गए पानी में बोली में भारी वृद्धि देखी गई - बोलीविया में विरोध प्रदर्शन
- मुंबई में जल विभाग पानी की आपूर्ति पर अपने खर्च पर आवरण करने के लिए पानी के शुल्कों के माध्यम से पर्याप्त पैसा बढ़ाता है।
- हैदराबाद - राजस्व संग्रह में आवृत्ति क्षेत्र और प्रदर्शन में वृद्धि हुई।
- चेन्नई - वर्षा जल संचयन के लिए शुरूआत - अनुबंध पर काम करने के लिए निजी कंपनियों की प्रयुक्त सेवा

स्वच्छता

- सुलभ, NGO 3 दशकों के लिए - भारत में कम जाति, कम आय वाले लोगों का सामना करने वाली स्वच्छता की समस्याओं का समाधान करने के लिए।

- 7,500 से अधिक सार्वजनिक शौचालय खंड और 1.2 मिलियन निजी शौचालयों का निर्माण, 10 लाख लोगों को स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना।

उपसंहार!

- गरीब इलाके में सेवाएं नहीं उपलब्ध हैं।
- निजी कंपनियों को सौंपना एक समाधान नहीं हो सकता है।
- न्यायसंगत तरीके से अधिकार प्रदान करना।